

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

देहरादून दिनांक 2/मार्च, 2008

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी 2008 से भुगतान।

गठित निम्नलिखित:-

- 1- शासनादेश संख्या-279/ xxvii(7)न.न./2008 दिनांक 01 अक्टूबर 2007
- 2- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय आप संख्या-1(1)/2008 संस्था-11 (ख)/ दिनांक 17 मार्च 2008

महोदय,

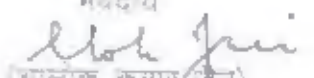
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कब से 01 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर 2007 एवं दिनांक 17 मार्च 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व पू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक 01 जनवरी 2008 से मंहगाई भत्ता 4% प्रतिशत से बढ़ाकर 47% प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/वस-42 (एन)/97 दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत /सशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2008, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2008 से दिनांक 31 मार्च 2008 तक की बड़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा बाह 01 अप्रैल 2008 का वेतन देय 30 अप्रैल 2008, से वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरिअर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोजता के अंश के साथ पेंशन सन्धवी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4- इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5- ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी 2008 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 89 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून 1998 के प्रस्तर-5 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय  
  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या /xxvii(7)/2008 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड औराव भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कौषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(व्यय नियंत्रण विभाग),कनरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कौषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।